भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1562

09.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

सार्वजनिक परिवहन उत्सर्जन पर पीएम ई-ड्राइव का प्रभाव

1562. **श्री पी. सी. मोहनः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की सार्वजनिक परिवहन उत्सर्जन पर पीएम ई-ड्राइव के दीर्घकालिक प्रभाव को मापने के लिए क्या योजना है;

(ख) भविष्य में कर्नाटक में पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार की क्या योजना है;

(ग) सरकार विशेषकर ई-बस बेड़े की शुरुआत के लिए कर्नाटक और विशेषकर बेंगलुरु के साथ समन्वय में सुधार के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों और बेंगलुरु जैसे महानगरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई रोडमैप है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) 29/09/2024 को अधिसूचित पीएम ई-ड्राइव स्कीम में 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। शुरुआत में, 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों - मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे में यह योजना लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।

(ख) और **(ग)** पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, बेंगलुरु को 4,500 ई-बसें आवंटित की गई हैं। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एकत्रीकरण मॉडल पर ई-बसों की खरीद कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा की जा रही है। ई-बसों के लिए सहायता प्रचालन व्यय (ओपेक्स)/सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर राज्य/शहर परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के माध्यम से प्रदान की जाती है। भारी उद्योग मंत्रालय और सीईएसएल इस स्कीम के तहत ई-बसों का प्रचालन शुरु करने के लिए बेंगलुरु सहित नौ शहरों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी उद्यमी भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों और बेंगलुरु जैसे महानगरीय शहरों सहित अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत ईवीपीसीएस के लिए प्रचालन दिशानिर्देश 26 सितंबर 2025 को जारी किए गए हैं।

****